[2019] 8 एस. सी. आर 1180

बिहार राज्य एवं अन्य

बनाम्

दिलीप कुमार एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 5205/2019)

18 जुलाई, 2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्तिगण]

बिहार नगर निकाय प्राथमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तें) नियम, 2006:नियम 10 अनुकंपा के आधार पर नौकरी तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी को नियम 10 के अनुसार अनुकंपा पर नगर शिक्षक के रुप में नौकरी दी गई। इसके बाद राज्य द्वारा जारी निर्देश कि पंचायत शिक्षकों और प्रखंड शिक्षकों के पद सरकार की सेवा में नहीं हैं, इस प्रकार उन पदों पर नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए अनुकंपा नियुक्ति समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं-राज्य सरकार के नियंत्रण वाले पदों पर अनुकंपा के आधार पर उनकी नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा परमादेश याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति-इसके बाद, राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए कि समिति पंचायत शिक्षकों/प्रखंड शिक्षकों/नगर शिक्षकों के पदों पर अनुकंपापूर्वक नियुक्तियां कर सकती है-खंडन्यायपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा-अपील पर, कहा:उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस तथ्य के बावजूद अपनी नियमित सेवा में प्रत्यर्थियों को नियुक्त करने का निर्देश देने में गलती की कि उनकी नियुक्तियाँ 2006 के नियमों के लागू होने के बाद की गई थीं-उनका मामला 2006 के नियमों द्वारा शासित होगा-उत्तरदाताओं ने नगर शिक्षकों के रूप में अपनी नियुक्तियों को स्वीकार कर लिया है। यह उनके लिए दावा करने के लिए खुला नहीं था, कि उन्हें राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त

किया जाए। साथ ही कोई भी कार्यकारी निर्देश नियमों का स्थान नहीं ले सकता था-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया, हालांकि, उत्तरदाताओं को उपयुक्त राहत के लिए राज्य सरकार से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित 1.1 बिहार नगर निकाय प्राथमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तें) नियम, 2006 के प्रवर्तन के साथ, नियम 10 अनुकंपा के आधार पर नगर शिक्षकों की नियुक्ति को नियंत्रित करता है। उत्तरदाताओं को 12 अप्रैल 2008 और 19 अगस्त 2008 2006 के नियमों के प्रवर्तन के बाद नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्तियाँ 2006 के नियमों के नियम 10 के अनुसार थीं।उत्तरदाताओं ने नियुक्तियों को स्वीकार कर लिया। एकल न्यायाधीश, 17 अक्टुबर 2008 के निर्देश में 2006 के नियमों पर निर्भरता रखने में पर ध्यान देने में विफल रहा।खंड पीठ का विचार था कि 22 जून 2009 के बाद के निर्देश द्वारा 17 अक्टूबर 2008 का निर्देश एकल न्यायाधीश द्वारा 15 मई 2009 को जारी किए गए परमादेश का पालन नहीं करेगा।खंड पीठ ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि दोनों प्रतिवादियों को 2006 के नियमों के नियम 10 के संदर्भ में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति स्वीकार करने के बाद, उनके लिए यह दावा करना खुला नहीं था, जैसा कि उन्होंने किया था, कि उन्हें बिहार सरकार की सेवा में नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कोई कार्यकारी निर्देश नियमों का स्थान नहीं ले सकता था। [कंडिका 9] [1186-जी-एच; 1187-ए-बी]

1.2 वर्तमान मामले में उत्तरदाताओं को 1 जुलाई 2006 के बाद नियुक्त किया गया है।इसलिए उनका मामला 2006 के नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। मुकेश के मामले में खंडपीठ के फैसले में निहित टिप्पणियां कि जिन अपीलार्थियों को 01.07.2006 के बाद नियुक्त किया गया था, जिस तारीख को नियम लागू हुए थे, वे नियमित वेतनमान पर नियुक्ति का दावा करने के हकदार नहीं हैं, जो तत्काल मामले में प्रत्यर्थियों पर लागू होंगे। उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को अपनी नियमित सेवा में प्रतिवादियों को नियुक्त करने का निर्देश देने में स्पष्ट रूप से त्रुटियां की, इस तथ्य के बावजूद कि उनकी नियुक्तियां 2006 के नियमों को लागू करने के बाद की गई थीं। उत्तरदाताओं ने नगर शिक्षक के रूप में अपनी

नियुक्तियों को विधिवत स्वीकार कर लिया।हालाँकि, प्रत्यर्थियों को विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 29655/2010 में पारित आदेशों के संदर्भ में और मुकेश के मामले में अपने फैसले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार उपयुक्त राहत के लिए राज्य सरकार से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है।उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। [कंडिकाएँ 11,12] [1189-ए-सी] डी

मुकेश बनाम बिहार राज्य (2017) 5 एस. सी. सी. 383-पर निर्भर। विश्वनाथ पांडे बनाम बिहार राज्य (2013) 10 एससीसी 545; बिहार राज्य बनाम पूजा मिश्रा एसएलपी (सी) संख्या 029453;/2015 बिहार राज्य बनाम संजय कुमार एसएलपी (सी) सं. 038376/2016-संदर्भित।

<u>वाद कानून संदर्भ</u>

(2013) 10 एस. सी. सी. 545	पारा 5	से संदर्भित
(2017) 5 एससीसी 383	पारा 11	पर निर्भर

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5205/2019

पत्र पेटेंट अपील संख्या 1589/2019 में उच्च न्यायालय, पटना के न्यायाधिकार और आदेश दिनांक 30.03.2015 से।

मनीष कुमार, गोपाल सिंह, अपीलार्थियों के लिए अधिवक्तागण

अभिजीत सिन्हा, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता ।

न्यायालय का निर्णय डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया ।

निर्णय

1. पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की एक खंडपीठ ने 30 मार्च, 2015 के अपने निर्णय द्वारा विद्वत एकल न्यायाधीश के विचारों की पुष्टि की और प्रत्यर्थियों को राज्य सरकार की सेवाओं में नियमित वेतनमान पर अनुकंपा पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश दिया, न कि नगर शिक्षक के पद पर जहां उन्हें नियुक्त किया गया था। यह निर्देश बिहार सरकार द्वारा 17 अक्टूबर, 2008 को जारी एक निर्देश पर आधारित था, जिसे वापस ले लिया गया है।खंडपीठ के आदेश से व्यथित बिहार राज्य अपील में है।

2. पहले प्रतिवादी के पिता की 7 मई 2006 को एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में रोजगार के दौरान मृत्यु हो गई। दूसरे प्रतिवादी की मां भी एक प्राथमिक विद्यालय में एक सहायक शिक्षक थीं, जब 9 सितंबर 2006 को उनकी मृत्यु हो गई थी। 25 जनवरी 2008 और 27 जून 2008 को, जिला अनुकंपा नियुक्ति समिति ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थियों के अनुरोध पर विचार किया। 12 अप्रैल 2008 को, पहले प्रतिवादी को बिहार नगर निकाय प्राथमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 10 के तहत नगर शिक्षक के पद पर रोजगार की पेशकश की गई। 19 अगस्त 2008 को, दूसरे प्रतिवादी को डीसीएसी की सिफारिश के आधार पर नगर शिक्षक के रूप में नियुक्ति की पेशकश की गई थी। 17 अक्टूबर 2008 को, बिहार सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक निर्देश जारी किया जिसमें कहा गया कि पंचायत शिक्षकों और प्रखंड शिक्षकों के पद सरकार की सेवा पर नहीं हैं, इसलिए उन पदों पर नियुक्तियों की सिफारिश करना डीसीएसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।निर्देश में इस प्रकार कहा गया हैः

> "....कि कुछ जिला अनुकंपा समितियों की बैठक के कार्यवृत्त के अवलोकन से यह स्पष्ट हो गया है कि जिला अनुकंपा समिति द्वारा अनुकंपा आधार पर पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक के पद के विरुद्ध नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है।पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक का पद सरकार का पद नहीं है और ऐसे पद पर अनुकंपा के

आधार पर नियुक्ति के लिए सिफारिश करना अनुकंपा समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

निर्देश के अनुसार, मुझे यह कहना है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक के पद पर नियुक्ति के खिलाफ नियुक्ति के लिए सिफारिश न की जाए।यदि ऐसी कोई सिफारिश की गई है तो उस पर जिला अनुकंपा समिति द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए और इसके द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार सिफारिश सुनिश्चित की जाए।"

3. प्रत्यर्थियों ने अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाहियां संस्थित की और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन पदों पर अनुकम्पा के आधार पर उनकी नियुक्ति के लिए परमादेश की मांग की। 15 मई 2009 को, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों की शिकायत को स्वीकार कर लिया कि नगर शिक्षक के जिन पदों पर उन्हें नियुक्त किया गया था, वे नियमित वेतनमान वाले सरकारी पद नहीं थे, बल्कि निश्चित परिलब्धियों वाले पद थे। विद्वत एकल न्यायाधीश के विचार से, यह दिनांक १७ अक्टूबर, २००८, के सरकारी निर्देश के विपरीत था। रिट याचिका की अनुमति देते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि डी.सी.ए.सी की सिफारिशों को दिनांक 17 अक्टूबर 2008 के निर्देशों के अनुसार “सख्ती से” लागू किया जाए।

4. इसके बाद 22 जून, 2009 को राज्य सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि नियमों के तहत गठित समिति के लिए पंचायत शिक्षकों/प्रखंड शिक्षकों/शहर के शिक्षकों के पदों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां करने की अनुमति है। निर्देश का प्रासंगिक हिस्सा नीचे उद्धृत किया गया हैः

"....यह प्रावधान बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक रोजगार और सेवा शर्तें नियम, 2006 के नियम 10 के अनुसार किया गया हैः-

“10 अनुकंपा के आधार पर रोजगार/नियुक्तिः पंचायत शिक्षक/प्रखंड शिक्षक के पद पर उपलब्ध रिक्ति के खिलाफ रोजगार/नियुक्ति शिक्षण या

गैर-शिक्षण कर्मचारियों के आश्रितों के संबंध में अनुकंपा के आधार पर निर्धारित पात्रता के अनुसार की जा सकती है, यदि वह इसके लिए स्पष्ट रूप से सहमति देता हैः-

नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक विभाग के परिपत्र के मद्देनजर उपरोक्त समिति द्वारा.अप्रशिक्षित आश्रितों के लिए नियुक्ति की तिथि से छह वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।"

बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक रोजगार और सेवा शर्तें नियम, 2006 के तहत भी इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। उपर्युक्त प्रावधानों में, 'समिति' शब्द का अर्थ नियम के तहत गठित समिति के संबंध में है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त नियमों के तहत गठित समिति द्वारा नियमित वेतन पर पंचायत शिक्षक/प्रखंड शिक्षक/शहर शिक्षक के पद पर अनुकंपा के आधार पर शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति की जा सकती है।"

5. एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ राज्य द्वारा एक लेटर्स पेटेंट अपील दायर की गई थी।खंडपीठ ने 30 मार्च, 2015 के अपने फैसले में कहा था कि चूंकि 2006 के नियमों के लागू होने से पहले सेवा में कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी और 17 अक्टूबर, 2008 के परिपत्र/निर्देश में स्पष्ट किया गया था कि सरकार की सेवा में किसी पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां करने की आवश्यकता थी, इसलिए रिट याचिका को सही तरीके से स्वीकार किया गया था।खंडपीठ ने निर्णय दिया कि 22 जून, 2009 को पहले के परिपत्र/निर्देश को याद करते हुए जारी किए गए निर्देश एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए आदेश के प्रभाव को कम नहीं करेंगे।उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विश्वनाथ पांडे बनाम बिहार राज्य 3 (विश्वनाथ पांडे) में, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश के विचार की पुष्टि की थी कि जहां 2006 के नियमों के लागू होने से पहले घटना हुई थी, वहां सरकार के तहत शिक्षक के रूप में नियुक्ति की जाएगी।

6. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि अनुकम्पा नियुक्तियां 2006 के नियमों द्वारा शासित होती हैं। नियम 10 के तहत, नगर शिक्षक अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए जाने चाहिए। इसके अलावा, नियम 20 सभी पिछले नियमों, प्रस्तावों, आदेशों और निर्देशों का स्थान लेता है। वर्तमान मामले में, यह आग्रह किया गया कि प्रत्यर्थियों ने उनकी नियुक्ति के लिए सहमति दी और नियम १० के संदर्भ में नगर शिक्षक के पद पर शामिल हुए। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश देना उचित नहीं था कि उनकी सेवाओं को नगर शिक्षक के पदों से हटाकर सरकार के नियंत्रण वाले पदों पर स्थानांतरित किया जाए। इस मामले के तथ्यों में, यह आग्रह किया गया है कि प्रत्यर्थियों को नगर शिक्षक के रूप में नियुक्ति की पेशकश 17 अक्टूबर 2008 के निर्देश से पहले की गई थी। इसके अलावा, नगर शिक्षक के रूप में नियुक्तियां 2006 के नियमों के अनुसार होने के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की सेवाओं में लेने का निर्देश देना उचित नहीं था। इस संदर्भ में, 3 अप्रैल 2017 को मुकेश बनाम बिहार राज्य (मुकेश) में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए एक फैसले पर भरोसा किया गया है, जहां विश्वनाथ पांडे में इस न्यायालय के फैसले पर विचार किया गया है और प्रतिष्ठित किया गया है।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता ने उन कारणों से उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया जिन्हें राहत प्रदान करने में महत्व दिया गया। विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीशों के समान निर्णयों के खिलाफ राज्य द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपीलों को खारिज कर दिया गया था, और इस न्यायालय ने राज्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद १३६ के तहत दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया.इस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर भरोसा किया गया है:

(i) बिहार राज्य बनाम पूजा मिश्रा (पूजा मिश्रा)

(ii) बिहार राज्य बनाम संजय कुमार (संजय कुमार)

उपरोक्त विशेष अनुमति याचिकाओं को क्रमशः 9 अक्टूबर, 2015 और 11 नवंबर, 2016 को खारिज कर दिया गया था।यह आग्रह किया गया कि इस न्यायालय को सिविल अपील को खारिज करके उसी कार्रवाई का पालन करना चाहिए।

8. 2006 के नियमों को 1 जुलाई, 2006 को अधिसूचित किया गया था।नियम 3 में प्राथमिक शिक्षकों का वर्गीकरण शामिल हैः

> "3. टाउन प्राथमिक शिक्षकों की श्रेणी-टाउन प्राथमिक शिक्षकों की दो श्रेणियां होंगीः-
>
> (ए) नगर शिक्षक (प्रशिक्षित)
>
> (बी) नगर शिक्षक (अप्रशिक्षित)

नियम 8 पात्रता की शर्तों का प्रावधान करता है।नियम 9 में नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रावधान है।नियम 10 में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

> "10. अनुकंपा के आधार पर नियुक्तिःनगर शिक्षक (प्रशिक्षित) और नगर शिक्षक (अप्रशिक्षित) के पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के लिए निर्धारित योग्यता के अनुसार अनुकंपा के आधार पर शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार दिया जा सकता है, यदि वह इसके लिए स्पष्ट रूप से अपनी सहमति देता है।सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित अन्य शर्तों के आलोक में उपरोक्त समिति द्वारा नियुक्ति की जा सकती है।रोजगार के बाद अप्रशिक्षित आश्रित अधिकतम 6 वर्षों के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे।"

नियम 20, जिसमें निरसन और बचत का प्रावधान है, निम्नलिखित शब्दों में हैः

> “20. निरसन और बचतः(i) इस नियम के लागू होने की तारीख से शहरी क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षकों/शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में सभी पिछले नियम, संकल्प, आदेश और निर्देश निरस्त समझे जाएंगे।
>
> (ii) लेकिन इस निरसन के बावजूद शिक्षकों के वेतन आदि और सेवा शर्तों के संबंध में किसी पूर्ववर्ती नियम, संकल्प, आदेश, निर्देश आदि पर कोई प्रभाव नहीं डाला जाएगा।"

9. 2006 के नियमों के प्रवर्तन के साथ, नियम 10 अनुकंपा के आधार पर नगर शिक्षकों की नियुक्ति को नियंत्रित करता है। 2006 के नियमों को लागू करने के बाद 12 अप्रैल 2008 और 19 अगस्त 2008 को प्रत्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी। उनकी नियुक्ति 2006 के नियमों के नियम 10 के अनुसार की गई थी। उत्तरदाताओं ने नियुक्तियों को स्वीकार कर लिया।विद्वत एकल न्यायाधीश, 17 अक्टूबर 2008 के निर्देश पर निर्भरता रखने में, 2006 के नियमों पर ध्यान देने में विफल रहे। खंडपीठ का विचार था कि एकल न्यायाधीश द्वारा 15 मई, 2009 को जारी किए गए आदेशों के अनुपालन को बाद के 22 जून, 2009 के निर्देश द्वारा 17 अक्टूबर, 2008 के निर्देश को वापस लेने से समाप्त नहीं किया जाएगा। खंडपीठ ने इस तथ्य की अनदेखी की कि दोनों प्रत्यर्थियों को 2006 के नियमों के नियम 10 के अनुसार नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति को स्वीकार करने के बाद उन्हें यह कहने का अधिकार नहीं था कि उन्हें बिहार सरकार की सेवा में नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कोई भी कार्यकारी निर्देश नियमों को अधिक्रमित नहीं कर सकता था।

10. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वत वकील ने पूजा मिश्रा और संजय कुमार के मामलों में राज्य द्वारा अनुच्छेद 136 के तहत दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हुए इस न्यायालय के 9 अक्टूबर, 2015 और 11 नवंबर, 2016 के आदेशों पर भरोसा किया है। उपर्युक्त आदेश, जिनके द्वारा इस न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया, प्रत्यर्थियों की प्रस्तुतियों में सहायता नहीं करेगा। यह साधारण कारण है कि बाद में, मुकेश में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने 3 अप्रैल, 2017 को अपने फैसले में 2006 के नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ इस विषय पर पूर्व निर्णय पर विचार किया। इस न्यायालय ने विनिश्चय से निष्कर्ष निकाला विश्वनाथ पांडे (जिस पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आक्षेपित निर्णय द्वारा भी भरोसा किया गया है)। मुकेश के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

> "आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सही निर्णय दिया कि अपीलकर्ताओं को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।" करुणामय नियुक्तियां भर्ती का

> एक स्रोत नहीं हैं और ये किसी ऐसे कर्मचारी के परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए की जाती हैं, जिसकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है।बिहार राज्य में अनुकंपा आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां सरकार द्वारा जारी अनुदेशों द्वारा शासित होती हैं। जिला करुणामय समिति द्वारा कुछ अपीलकर्ताओं को नियमित आधार पर तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था। हालांकि, उन्हें एक निर्धारित वेतन पर प्रखंड शिक्षक/पंचायत शिक्षक/नगर शिक्षक आदि के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलकर्ताओं को एक निर्धारित वेतन पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था और वे नियमित आधार पर या प्रखंड शिक्षक/पंचायत शिक्षक/नगर शिक्षक आदि के पदों में नियमित वेतनमान के भुगतान के हकदार हैं, जिनमें वे वर्तमान में काम कर रहे हैं। कुछ अपीलकर्ता जिन्हें तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था, लेकिन जिन्हें निश्चित वेतन पर प्रखंड शिक्षक/पंचायत शिक्षक/नगर शिक्षक आदि के रूप में नियुक्त किया गया था, वे इसी तरह विश्वनाथ पांडे के स्थान पर स्थित हैं और वे नियमित वेतनमान पर नियुक्ति के हकदार हैं।"

1 जुलाई 2006 (2006 के नियमों के प्रवर्तन की तारीख) के बाद नियुक्त किए गए अपीलार्थियों के संबंध में, इस न्यायालय ने कहाः

> “अन्य अपीलकर्ता जिनकी नियुक्ति 01.07.2006 के बाद की गई थी, वे उन लोगों को दी गई राहत के हकदार नहीं हैं, जिनकी नियुक्ति उस तिथि से पहले तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए की गई थी। बिहार राज्य और अन्य बनाम राजीव रन विजय कुमार (2010) 3 पीएलजेआर 294 (एफबी) में रिपोर्ट की गई पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी पदों पर नियुक्त होने का कानूनी अधिकार नहीं है। अनुकंपा के आधार पर उनकी नियुक्तियां बिहार

पंचायत प्राथमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तें) नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके बाद 'नियम' कहा गया है) के अनुसार की जाएंगी, जो 1 जुलाई, 2006 से लागू हुआ था। उक्त नियमों के नियम 10 में शिक्षण/गैर-शिक्षण के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने का प्रावधान है। इस तरह की नियुक्तियां नियमों के तहत गठित समिति द्वारा निर्धारित वेतन पर ही की जा सकती हैं। अपीलकर्ता जिन्होंने 01.07. 2006 से पहले तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित नहीं किए गए हैं, वो विश्वनाथ पांडे के मामले में शामिल नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय के अंतर्गत आते हैं।वे उन लोगों के समान नहीं हैं जिनकी तीसरी श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिश 07. 2006 से पहले की गई थी। अपीलकर्ता, जिनकी नियुक्ति 01.07.2006 के बाद की गई थी, वह नियमित रूप से नियुक्ति का दावा करने के हकदार नहीं हैं। यह नोट करना प्रासंगिक है कि पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी.उक्त एसएलपी को याचिकाकर्ताओं को उचित राहत के लिए सरकार से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था।"

(महत्वपूर्ण माना गया)

11. बेशक, वर्तमान मामले में भी, प्रत्यर्थियों को 1 जुलाई, 2006 के बाद नियुक्त किया गया है। अतः उनका मामला 2006 के नियमों द्वारा शासित होगा। मुकेश में खंड पीठ के निर्णय में निहित उपरोक्त टिप्पणियां वर्तमान मामले में प्रत्यर्थियों पर लागू होंगी। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के बावजूद कि उनकी नियुक्तियां 2006 के नियमों के लागू होने के बाद की गई थीं, बिहार सरकार को अपनी नियमित सेवा में प्रतिवादियों को नियुक्त करने का निर्देश देने में स्पष्ट रूप से त्रुटियां की थी। प्रत्यर्थियों ने नगर शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्तियों को विधिवत स्वीकार किया। तथापि, हम प्रत्यर्थियों को यह स्वतंत्रता प्रदान करते हैं कि वे 2010-7 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 29655 में पारित आदेशों के

संदर्भ में और उसी शर्तों में जो इस न्यायालय द्वारा मुकेश मामले में दिनांक 3 अप्रैल, 2017 को अपने निर्णय में आदेश दिया गया था, उपयुक्त राहत के लिए राज्य सरकार से संपर्क करें।

12. सिविल अपील को अनुज्ञात किया जाता है। उच्च न्यायालय के 30 मार्च, 2015 के फैसले और आदेश को रद्द किया जाता है। लागत-दण्ड के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

13. प्रत्यारोपण के लिए आवेदन का निपटान कर दिया गया है।लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, का भी निपटान किया जाता है।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़], न्यायमूर्ति

[इंदिरा बनर्जी], न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

18 जुलाई, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।